Indian J. Soc. & Pol. 13 (01):119-120: 2026 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 January 2026 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की भूमिका का एक अध्ययन

रजनीकान्त श्रीवास्तव[1], अनिल कुमार[2]

[1]प्राचार्य,आर एम पी पी जी कॉलेज सीतापुर, उ.प्र., भारत
[2]शोधार्थी,लखनऊ विश्वविद्यालय ,लखनऊ, उ.प्र., भारत

ABSTRACT

भारत में रसोई गैस को लंबे समय तक एक शहरी सुविधा माना जाता था, जिससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं वंचित थीं। पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, उपले आदि का प्रयोग महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होता रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इस स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर उन्हें धुएँ से मुक्ति, समय की बचत और रसोई में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई है। यह योजना केवल एक गैस सिलेंडर तक सीमित न रहकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बनी है। इससे महिलाओं की सामाजिक, स्वास्थ्यगत और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। इस शोध का उद्देश्य उज्ज्वला योजना के प्रभावों का अध्ययन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसकी वास्तविक भूमिका को उजागर करना है।

KEYWORDS: *उज्जवला योजना, महिला सशक्तिकरण,स्वास्थ्य,स्वरोजगार*

भारत के ग्रामीण और वंचित परिवारों की महिलाएं दशकों से खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, और कोयला पर निर्भर थीं। ये ईंधन जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न करते हैं, जिससे घरों में वायु प्रदूषण फैलता है और महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ठोस ईंधनों के जलने से होने वाला इनडोर प्रदूषण हर साल 4 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बनता है। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे होते हैं, जो खाना बनाते समय घंटों तक जहरीले धुएं के संपर्क में रहते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े भी दिखाते हैं कि ग्रामीण भारत में लाखों घरों में खाना बनाते समय वायु गुणवत्ता बेहद खराब होती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ, आंखों की समस्याएं, और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आम हो जाती हैं।ऐसे में, एक प्रभावी और दूरगामी समाधान की आवश्यकता महसूस की गई, जो महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा तक पहुंच प्रदान कर सके।

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना था, ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्वच्छ रसोई ईंधन का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को दिया जाता है, जिनकी पहचान सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना डेटा के आधार पर की जाती है। इस तरह, उज्ज्वला योजना केवल एलपीजी कनेक्शन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सबसे जरूरतमंद तबकों को मुख्यधारा में लाने का एक प्रभावशाली प्रयास है।

योजना का क्रियान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया, और इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को ₹1600 की आर्थिक सहायता, मुफ्त गैस चूल्हा, और पहली गैस रिफिल दी गई। इस योजना के तहत 2021 तक 8 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिससे योजना ने भारत के सतत विकास लक्ष्यों जैसे स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया।2 हालांकि, योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आईं, जैसे सिलेंडर रिफिल की लागत, दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच, और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता की कमी। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई, जिसमें मुफ्त पहली रिफिल, सरल दस्तावेज प्रक्रिया, और अधिक लाभार्थियों को जोड़ने पर जोर दिया गया।3

यद्यपि भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला और उपलों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन पारंपरिक ईंधनों के जलने से निकलने वाला धुआं न केवल महिलाओं के फेफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि घर के अन्य सदस्यों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है।

इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ इस शोध पत्र का लेखन किया गया है।

पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी और उपले इकट्ठा करने में महिलाओं का काफी समय लगता था। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद, महिलाओं ने इस बचे हुए समय का उपयोग छोटे व्यवसाय, कृषि कार्यों या परिवार की आजीविका बढ़ाने के लिए किया। समय की बचत और उत्पादकता में वृद्धि हुई

1: Corresponding Author

है। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट (2021) के अनुसार, उज्ज्वला योजना से 65 प्रतिशत महिलाओं ने औसतन 2–3 घंटे प्रतिदिन बचाए, जिसे उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में लगाया।4एलपीजी के उपयोग से समय बचने के साथ–साथ स्वास्थ्य में सुधार होने से महिलाओं ने छोटे स्तर पर स्वरोजगार की शुरुआत की, जैसे कि सिलाई, बुनाई, पापड़ बनाना, या कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग। यह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। रिसर्चगेट की एक रिपोर्ट में पाया गया कि उज्ज्वला योजना के बाद से अधिक महिलाओं ने घरेलू स्तर पर कुटीर उद्योग शुरू किए, जिससे उनके मासिक आय में 20–30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।5

उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं, इससे उनके भीतर एकस्वामित्व की भावना विकसित होती है। इससे वे घर के वित्तीय निर्णयों में अधिक मुखर हुईं और परिवार के बजट और बचत की प्लानिंग में भागीदारी बढ़ी। उज्ज्वला लाभार्थी परिवारों की 70 प्रतिशत महिलाएं अब वित्तीय निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।6 एलपीजी के इस्तेमाल से खाना बनाने में लगने वाला समय घटने के कारण महिलाओं को कृषि और डेयरी जैसी ग्रामीण आजीविका गतिविधियों में योगदान करने का अवसर मिला। इससे घरेलू आय में वृद्धि हुई और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों की उ कृषि उत्पादकता में 15.3 की वृद्धि हुई, क्योंकि महिलाएं अधिक समय खेतों में लगा पा रही थीं। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी एलपीजी के कारण घर के कामों में लगने वाला समय घटने से महिलाएं बाहर जाकर मजदूरी या अन्य नौकरियों में भी हिस्सा ले सकीं। इससे उनकी व्यक्तिगत आय बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (2023) के अनुसार, उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं में 25 प्रतिशत की वृद्धि कार्यबल में भागीदारी के रूप में दर्ज की गई।7

पारंपरिक चूल्हे से निकलने वाला धुआं फेफड़ों में सूजन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों की बड़ी वजह था।वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिलाओं को इनडोर वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं थीं, जो एलपीजी अपनाने के बाद 30–40 प्रतिशत तक कम हुई हैं।धुएं के लगातार संपर्क में रहने से आंखों में जलन, मोतियाबिंद, और त्वचा की जलन की समस्याएं होती थीं। एलपीजी उपयोग के बाद महिलाओं ने आंखों में जलन और सिरदर्द की घटनाओं में 45 प्रतिशत की गिरावट देखा गयाद्य जंगल से लकड़ी लाने के लिए महिलाओं को दूर–दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, जिससे जानवरों के हमले या दुर्घटनाओं का खतरा रहता था। एलपीजी मिलने के बाद यह जोखिम भी काफी कम हुआ।8

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह योजना न केवल स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, बल्कि महिलाओं को 'गृहलक्ष्मी' के रूप में मान्यता दिलाने में भी सहायक रही है, जो परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली की संरक्षक हैं। पारंपरिक चूल्हों के धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से मुक्ति पाकर, महिलाएं अब स्वस्थ जीवन जी रही हैं। इसके अतिरिक्त, खाना पकाने में लगने वाले समय में कमी आने से वे अन्य सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो पा रही हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और समय की बचत के कारण, महिलाएं अब पंचायत बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इससे वे समुदाय के निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में शामिल होकर स्थानीय विकास में योगदान दे रही हैं। यह सहभागिता उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देती है और सामुदायिक विकास में उनकी भूमिका को सशक्त बनाती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारत की ग्रामीण और वंचित महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, आर्थिक सहायता, और पहली गैस रिफिल की सुविधा मिली, जिससे वे पारंपरिक और प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भर रहने की मजबूरी से मुक्त हुईं। यह योजना न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सफल रही, बल्कि उनके समय प्रबंधन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, और सामाजिक सशक्तिकरण को भी नई दिशा दी।एलपीजी के उपयोग से इनडोर वायु प्रदूषण में कमी आई, जिससे श्वसन रोग, आंखों की जलन, और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा घटा। खाना पकाने में लगने वाला समय कम होने से महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार, और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला।

इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के नाम पर जारी किए गए, जिससे उनके भीतर स्वामित्व और निर्णय लेने की भावना विकसित हुई। वे परिवार के बजट, बचत, और स्वास्थ्य संबंधी फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान बढ़ा। ''उज्ज्वला दीदी'' पहल के माध्यम से महिलाएं समुदाय में एलपीजी सुरक्षा और उपयोगिता की जानकारी फैलाने लगीं, जिससे उनकी सामुदायिक पहचान और नेतृत्व क्षमता मजबूत हुई।

अंततः, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने साबित कर दिया कि जब नीतियों के केंद्र में महिलाओं को रखा जाता है, तो वे पूरे समाज के उत्थान का माध्यम बन सकती हैं। इस योजना ने महिलाओं को स्वस्थ, सुरक्षित, और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया, जिससे वे न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकीं।

REFERENCES

उत्तर प्रदेश सरकार, ऊर्जा उपभोक्ता सहायता योजना, प्रेस विज्ञप्ति, 1 मई 2016

भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, 10 अगस्त 2021। https://www.pmuy.gov.in/